Title: Issue relating to non-receipts of grants by the 'Ashramahales' run by NGOs.

श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 7 मार्च से महाराष्ट्र के एनजीओज के कुछ कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हुए है, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उन्होंने चार साल पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता के एडवर्टाइजमैंट पर आश्रम स्कूल खोले थे, लेकिन चार साल से उनको कुछ सहायता नहीं मिली है। तकरीबन 10 हजार अनुसूचित जाति के लड़के उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आज उनका भविष्य अंधकार में है। वहां पर 1500 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन आश्रम स्कूलों को पैसा दिया जाये तथा उनका जो पिछला बकाया है, वह भी दिया जाये क्योंकि इसी तरह उन बच्चों की पढ़ाई हो सकती है अन्यथा उन 10 हजार अनुसूचित जाति के लड़के बेसहारा हो जायेंगे और उनकी पढ़ाई खत्म हो जायेगी। सरकार कहती है कि वहां लिट्रेसी ज्यादा है लेकिन उनका कहना गलत है। वहां लिट्रेसी कम है क्योंकि वे अनुसूचित जाति के लोग है जिनमें लिट्रेसी नहीं है। ऐसे लड़कों को पढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाना चाहिए।